two States to complete this project in view of the power shortage in the country and in view of the fact that it is a major project which is capable of producing over 1,000 megawats of electricity.

MR. SPEAKER: Earlier, the better.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: If it is a Central Project, the question of finance from the States does not arise. Now, the latest development is that Himachal Pradesh and Haryana want to do the job themselves and they have given us a new offer. We are starting with this new offer. It will go to the Planning Commission.

MR. SPEAKER: Decide at the earliest.

Nationalisation of Oil India Limited

+

*213. SHRI SURYA NARAYAN SINGH:

SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalisation of Oil India Limited has been delayed;

(b) if so, when was the decision taken to this effect; and

(c) the reasons for delay in its implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Negotiations with B.O.C. for the takeover of whole or part of their interest in O.I.L. started in September, 1976.

(c) Various aspects of the issue are under the active consideration of the Government and it is not in public interest to disclose any details at this stage.

श्री सूर्य नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1976 से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि आयल इन्डिया का नेशनेलाइजेशन किया जाए और 1976 में जब पेट्रोलियम मिनिस्टर, श्री के० डी० मालवीय थे, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि राष्ट्र के हित में बी० ओ० सी० राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त बहुगुणा जी ने भी यह आश्वासन दिया था और इस बात की जांच करने के लिए एक पैनल भी बनाया था कि कितना शीघ्र और किस तरह से इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इस सब को चार-पांच साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जबकि सरकार की नीति भी एक्सप्लोरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने की है। फिर ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ? इसके राष्ट्रीयकरण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, यह मामला गवर्नमेंट के एक्टिव कंसीडेशन में है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब तक जो इसमें समय लगा है उसकी कई वजूहात हैं। असम आयल कम्पनी का मामला भी आया और यह मामला भी था। ये सारे मामले मिला कर के करने में समय लगता है और इसीलिए इसमें समय लगता गया। यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है और इसमें कुछ महीने और लगेंगे।

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या बी० ओ० सी० से कम्पेनसेशन के सवाल पर हिच हो रही है ? बर्मा आयल कम्पनी और आयल इंडिया कम्पनी के 50-50 परसेंट इक्विटी शेअर्स हैं और कुल मिला कर 28 करोड़

रुपये की इक्विटी पूंजी है। बी० ओ० सी० के 14 करोड़ रुपये के इक्विटी शेअर्स हैं फिर क्या कारण है कि राष्ट्र के हित में इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ? इस कम्पनी ने काफी मुनाफा भी कमा लिया है। क्या यह सही है कि कम्पनी 40 करोड़ रुपये के कम्पेनसेशन की मांग कर रही है ? क्या इसी कारण से इसके राष्ट्रीयकरण में देरी हो रही है ?

श्री दलबीर सिंह : हम इसमें कार्यवाही तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा मामला विचाराधीन है।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: When ESSO and other foreign oil companies were nationalised, one criterion was fixed and they were taken over. May I know from the hon. Minister whether, in the case of BOC and Assam Oil Company which, for long years, have taken out whatever proceeds are possible from this country, and different criterion is being adopted because of which the matter is being delayed or whether the same criterion which was applied to ESSO and others is being applied here also.

SHRI DALBIR SINGH: It will become possible in the near future.

MR. SPEAKER: His question is whether there is any deviation from that concept.

SHRI DALBIR SINGH: No deviation.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को लेने में अब तक क्या हिच है ? क्या यह कम्पनी आपसे 40 करोड़ रुपये की मांग कर रही है यह बताइये ? यदि इतना नहीं मांग रही है तो कितनी राशि मांग रह है ?

श्री दलबीर सिंह : वे कितना मांग रहे हैं, उस पर निर्णय नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री वे कितना मांग रहे हैं यह तो हमें बता दीजिए, यह जानने का हमारा हक है।

श्री दलबीर सिंह : मांगने को तो बी० ओ० सी० कुछ भी मांग सकती है।

Views of Chief Justice of Indian Administration of Justice

*215. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken into consideration the views expressed by the Chief Justice of India for decentralisation of the administration of justice by setting up of "Naya Panchayats" in the country;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b). The system of Nyaya Panchayats was considered by the Bhagwati Committee in Chapter VI of their report on "National Juridicare Equal Justice—Social Justice" submitted in August, 1977. This subject had also been considered in the Report of the Committee on Panchayat Raj Institutions submitted in August, 1978. A model bill is being drafted in the Ministry of Rural Reconstruction commending to State Governments that the existing State Legislation may be brought in line with the model legislation and States which do not have legislation on the subject may undertake legislation on the lines of the model bill.

(c) Does not arise.

श्री चित महाटा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि न्याय-पंचायत का माडल बिल का ड्राफ्ट कब शुरु हुआ और कब तक वह कामयाब होगा ?